

विचार

क्यों नहीं पहुंच पातीं सरकारें घरों की दहलीज तक?

भारतीय राजनीति में महिलाओं के सशक्तीकरण की बातें खूब होती हैं। चुनावी घोषणापत्रों में उनके लिए वादे भी किए जाते हैं, परंतु चुनाव बीतते ही वायदों पर धूल की परत जम जाती है। शायद ही कोई जनप्रतिनिधि उनके दुख-दर्द को सुनने, उनकी अपेक्षाओं को समझने के लिए घर की दहलीज तक जाता हो? यह एक कड़वी सच्चाई है जिसे देश के अधिकांश राज्यों में महिलाओं ने जिया है। लेकिन तारीफ करनी होगी बिहार की जिसने इस परिपाटी को तोड़कर एक नई मिसाल कायम की है। एक ऐसा प्रदेश, जिसने दशकों तक महिलाओं को पुरुषों के निर्देशों पर मताधिकार का प्रयोग करते देखा, आज वहाँ महिला सशक्तीकरण की एक ऐसी नई इबारत लिख रहा है, जो देश के लिए एक अनुकरणीय मॉडल बन चुकी है। इस परिवर्तनकारी यात्रा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव %महिला संवाद कार्यक्रम है जिसे विगत 18 अप्रैल से प्रदेश में ग्राम स्तर पर शुरू किया गया। यह पहल केवल एक सरकारी कावायद नहीं, बल्कि महिलाओं को केंद्र में रखकर सामाजिक बदलाव को गति देने का एक सशक्त माध्यम है। यह कार्यक्रम प्रदेश की बेटियों, माताओं और बहनों की आवाज़ को गंभीरता से सुनने, समझने और भविष्य की नीतिगत व प्रशासनिक पहलों को आकार देने का एक महत्वपूर्ण मंच बन गया है। यह संतोष का विषय है कि अब तक 38 जिलों में 52,468 महिला संवाद कार्यक्रमों का सफल आयोजन हो चुका है, जिसमें कुल 1 करोड़ 13 लाख से अधिक महिलाओं ने उत्साह के साथ भाग लिया। यह सच्चा इस बात का भी जीवंत प्रमाण है कि प्रदेश की महिलाएं अब अपनी आवाज़ उठाने और सरकार से सीधे जुड़ने को लेकर कितनी उत्सुक और जागरूक हैं। दरभंगा से लेकर पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, पश्चिमी चंपारण, गया, पूर्णिया, समस्तीपुर, नालंदा और वैशाली तक, हर जगह महिलाओं ने बेबाकी से अपनी बात रखी है। उन्होंने नीति-निर्माताओं को यह समझने का अवसर दिया है कि महिला सशक्तीकरण की दिशा में आगे किन प्राथमिकताओं के साथ कदम बढ़ाए जाएं। महिला संवाद की यह पृष्ठभूमि आकस्मिक नहीं है। नीतीश कुमार के कार्यकाल को ध्यान से देखें तो पता चलता है कि सबसे पहले, लड़कियों में शिक्षा की अलाख जगाने पर ज़ेर दिया गया। जहां वर्ष 2000 के आसपास बिहार में लड़कियाँ सरकारी स्कूलों में कम जाती थीं, वहीं वर्ष 2006 में मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना की शुरुआत ने ऋतिकारी परिवर्तन लाया। इस योजना ने लड़कियों को शिक्षा के लिए प्रेरित किया, जिससे वे दूर-दराज के गांवों से भी साइकिल चलाकर स्कूल पहुंचने लगीं। इसकी सफलता ने देश के अन्य राज्यों को भी डूसे अपनाने के लिए प्रेरित किया।

शिक्षा के साथ-साथ महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकारी नौकरियों में भी ऐतिहासिक कदम उठाए गए। वर्ष 2013 से पुलिस भर्ती में महिलाओं को 35 प्रतिशत आरक्षण दिया जा रहा है। 2016 से सभी प्रकार की सरकारी नियुक्तियों में महिलाओं को 35 प्रतिशत का आरक्षण दिया जा रहा है, और प्राथमिक शिक्षक नियोजन में तो 50 प्रतिशत आरक्षण देकर उन्हें सशक्ति किया गया है। महिलाओं के सशक्तीकरण और गरीबी उम्मूलन में जीविका स्वयं सहायता समूह का गठन भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। वर्ष 2006 में विश्व बैंक से ऋण लेकर शुरू की गई जीविका ने ग्रामीण महिलाओं की आर्थिक उन्नति के लिए वरदान साबित हुई है। मुख्यमंत्री द्वारा इन महिलाओं को दिया गया जीविका दीदी नाम आज एक पहचान बन चुका है। वर्तमान में बिहार में 10 लाख 64 हजार स्वयं सहायता समूह काम कर रहे हैं, जिनसे 1 करोड़ 35 लाख से अधिक जीविका दीदियाँ जुड़ी हैं। जीविका से जुड़कर ये महिलाएं लघु उद्योगों और कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित कर अपने और अपने समुदाय के जीवन स्तर में सुधार ला रही हैं। महिला संवाद कार्यक्रम में प्रदेश की महिलाओं ने कई महत्वपूर्ण और व्यवहारिक मांगें रखी हैं, जो उनकी दूरदृष्टि और आकांक्षाओं को दर्शाती हैं। उनकी सबसे प्रमुख मांग स्वरोजगार से जुड़ी है, जिसमें स्वयं सहायता समूहों के लिए सस्ते ब्याज दरों पर ऋण और जीविका दीदी की रसीद जीविका दीदी हाट जैसी पहल शामिल हैं।

पीएम मोदी की अफीकी व दक्षिण अमेरिकी देशों की यात्रा से ग्लोबल साउथ को मिलेगी मजबूती, भारत की वैश्विक धमक बढ़ेगी

जब वैश्विक पटल पर अमेरिका और चीन एक दूसरे पर पलटवार करने के लिए रूस के मित्र भारत को अपने-अपने खेमे में मिलाने के लिए तरह-तरह की भारत विरोधी चालें चल रहे हैं, वहीं भारत अपनी सधी चाल से रूस को भी हैरत में डालते हुए ग्लोबल साउथ यानी तीसरी दुनिया के देशों पर निरंतर अपनी पकड़ मजबूत करता जा रहा है। इसलिए पीएम नरेंद्र मोदी विगत 11 वर्षों से लगातार वैश्विक यात्रा कर रहे हैं और भारत की वैश्विक स्थिति को काफी मजबूती प्रदान कर चुके हैं। उनकी कोशिश है कि भारत दुनिया के गुटनिरपेक्ष देशों को एक सशक्त नेतृत्व प्रदान करे और अपने साथ साथ सभी देशों का आशातीत विकास करे।



इससे सत्य व अहिंसा की वैश्विक भावना को भी मजबूती मिलेगी। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अपने 9 दिवसीय विदेश दौरे पर 2 जुलाई को घाना की राजधानी अकरा के लिए रवाना हो गए। उनकी इस यात्रा का उद्देश्य भी भारत के वैश्विक साझेदारी को ग्लोबल साउथ और अटलांटिक के दोनों पक्षों के साथ संबंधों को मजबूत करना है। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री की इस यात्रा में घाना, त्रिनिदाद और टोंबैगो, अर्जेंटीना, ब्राजील और नामीबिया का दौरा शामिल हैं। पीएम मोदी ने इन देशों को भारत की विदेश नीति के लिए महत्वपूर्ण साझेदार बताया, जो ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और बहुपक्षीय सहयोग से जुड़े हैं। अपने इस विदेश यात्रा के दौरान पीएम मोदी अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के कई देशों की यात्रा करेंगे, जिसके अपने वैश्विक मायने हैं। इसके अलावा वह ब्राजील की मेजबानी में हो रहे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भी शामिल होंगे, जहां वह ग्लोबल साउथ से जुड़े मुद्दों को उठाएंगे। स्पष्ट है कि उनकी यह यात्रा ग्लोबल साउथ में भारत की धमक बढ़ाएगी। प्राप्त जानकारी के मुताबिक, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अफ्रीकी देश घाना की पहली द्विपक्षीय यात्रा की

शुरूआत 2-3 जुलाई को की। वह पिछले तीन दशक में यह आने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति जॉन ड्रामानी महामा के निमंत्रण पर मैं 2-3 जुलाई को घाना का दौरा करूँगा।

घाना ग्लोबल साउथ में एक मूल्यवान साझेदार है और अफ्रीकी संघ और पश्चिम अफ्रीकी राज्यों के आर्थिक समुदाय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उन्होंने निवेश, ऊर्जा स्वास्थ्य, सुरक्षा और विकास साझेदारी जैसे क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाने की उम्मीद जताई। उन्होंने कहा कि घाना की संसद में बोलना मेरे लिए सम्मान की बात होगी। बता दें कि घाना के राष्ट्रपति जान महामा 2015 में इंडिया-अफ्रीका फोरम समिट के लिए भारत आए थे। वह जनवरी 2025 में तीसरी बार राष्ट्रपति चुने गए हैं। चूंकि घाना भारत को बड़े पैमाने पर वस्तुओं का निर्यात करता है और पश्चिम अफ्रीका की सबसे तेजी से बढ़ रही अर्थव्यवस्थाओं में से वह एक है लिहाजा दोनों देश व्यापार और निवेश बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। घाना से भारत के आयात में 70 प्रतिशत हिस्सेदारी गोल्ड की है। प्रधानमंत्री मोदी महामा के साथ द्विपक्षीय

मध्यमवर्गीय परिवार नहीं फँसे ब्रण के जाल में



प्रह्लाद सबनानी

हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो दर में 50 आधार बिंदुओं की कमी की है। इसके साथ ही, निजी क्षेत्र के बैंकों, सरकारी क्षेत्र के बैंकों एवं क्रेडिट कार्ड कम्पनियों सहित अन्य वित्तीय संस्थानों ने भी अपने ग्राहकों को प्रदान की जा रही ऋणाराशि पर लागू ब्याज दरों में कमी की घोषणा करना प्राम्भ कर दिया है ताकि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा रेपो दर में की गई कमी का लाभ शोध ही भारत में ऋणदाताओं तक पहुंच सके एवं इससे अंततः देश की अर्थव्यवस्था को बल मिल सके। भारत में चूंकि अब मुद्रा स्फीति की दर नियंत्रण में आ गई है, अतः आगे आने वाले समय में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा रेपो दर में और अधिक कमी की जा सकती है। इस प्रकार, बहुत सम्भव है ऋणाराशि पर लागू ब्याज दरों में कमी के बाद कई नागरिक जिन्होंने पूर्व में कभी बैंकों से ऋण नहीं लिया है, वे भी ऋण लेने का प्रयास करें। बैंक से ऋण लेने से पूर्व इस बात का ध्यान रखना आवश्यक है कि इस ऋण को चुकता करने की क्षमता भी ऋणदाता में होनी चाहिए अर्थात् ऋणदाता की पर्याप्त मासिक आय होनी चाहिए ताकि बैंकों द्वारा प्रदत्त ऋण की किशत एवं ब्याज का भुगतान पूर्व निर्धारित समय सीमा के अंदर किया जा सके। इस सदर्भ में विशेष रूप से युवा ऋणदाताओं द्वारा क्रेडिट कार्ड के उपयोग पश्चात् संबंधित राशि का भुगतान समय सीमा के अंदर अवश्य करना चाहिए क्योंकि अन्यथा क्रेडिट कार्ड एजेंसी द्वारा चूंकि की गई राशि पर भारी मात्रा में ब्याज वसूला जाता है,

बैंकों से लिए गए ऋण की मासिक किश्त एवं इस ऋणराशि पर ब्याज का भुगतान यदि निर्धारित समय सीमा के अंदर नहीं किया जाता है तो चूंकर्ता ऋणदाता से बैंकों द्वारा दंडात्मक ब्याज की वसूली की जाती है। इसी प्रकार, कई नागरिक जो क्रेडिट कार्ड का उपयोग करते हैं एवं इस क्रेडिट कार्ड के विरुद्ध उपयोग की गई राशि का भुगतान यदि वे निर्धारित समय सीमा के अंदर नहीं कर पाते हैं तो इस राशि पर चूंक किए गए क्रेडिट कार्ड धारकों से भारी भरकम ब्याज की दर से दंड वसूला जाता है। कभी कभी तो दंड की यह दर 18 प्रतिशत से 24 प्रतिशत के बीच रहती है। क्रेडिट कार्ड का उपयोग करने वाले नागरिक

कई बार इस उच्च व्याज दर पर वसूली जाने वाली दंड की राशि से अनभिज्ञ रहते हैं। अतः बैंकों से ली जाने वाली ऋणराशि एवं क्रेडिट कार्ड के विरुद्ध उपयोग की जाने वाली राशि का समय पर भुगतान करने के प्रति ऋणदाताओं को सजग रहने की आवश्यकता है।

कुल मिलाकर यह ऋणदाताओं के हित में है कि वे बैंक से लिए जाने वाले ऋण की राशि तथा व्याज की राशि एवं क्रेडिट कार्ड के विरुद्ध उपयोग की जाने वाली राशि का पर्याप्त निर्धारित एवं उचित समय सीमा के अंदर भुगतान करें क्योंकि अन्यथा की स्थिति में उस चूकर्ता नागरिक की क्रेडिट रेटिंग पर विपरीत प्रभाव पड़ता है एवं आगे आने वाले समय में उसे किसी भी तिनीय संस्थान से ऋण पास करने में कठिनाई का सम्भावना

करना पड़ सकता है एवं बहुत सम्भव है कि भविष्य में किसी भी वित्तीय संस्थान से ऋण प्राप्त ही न हो सके।

ऋग्वादाता यदि किसी प्रामाणिक कारणवश अपनी किशत व्याज का बैंकों अथवा क्रेडिट कार्ड कम्पनी को समय भुगतान नहीं कर पाता है और उसका ऋग्वा खाता यदि निष्पादनकारी आस्ति में परिवर्तित हो जाता है तो इस संदर्भ चूककर्ता ऋग्वादाता द्वारा बैंकों को समझौता प्रस्ताव दिए जाने प्रावधान भी है। इस समझौता प्रस्ताव के माध्यम से चूककर्ता ऋग्वादाता द्वारा सम्बन्धित बैंक अथवा क्रेडिट कार्ड कम्पनी मासिक किशत एवं व्याज की राशि को पुनर्निर्धारित किए जाएंगे के सम्बन्ध में निवेदन किया जा सकता है। परंतु, यदि ऋग्वादाता की परी गश्ति ल्याज सहित अटा करने में सक्षम नहीं है

चूक की गई राशि में से कुछ राशि की छूट प्राप्त करने एवं शेष राशि को एकमुश्त अथवा किश्तों में अदा करने के सम्बन्ध में भी समझौता प्रस्ताव दे सकता है। ऋण की राशि अथवा व्याज की राशि के सम्बन्ध के प्राप्त की गई छूट की राशि का रिकार्ड बनता है एवं समझौता प्रस्ताव के अंतर्गत प्राप्त छूट के चलते भविष्य में उस ऋणदाता को बैंकों से ऋण प्राप्त करने में कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है, इस बात का ध्यान चूककर्ता ऋणदाता को खबर चाहिए। अतः जहां तक सम्भव को ऋणदाता द्वारा समझौता प्रस्ताव से भी बचा जाना चाहिए एवं अपनी ऋण की निर्धारित किश्तों एवं व्याज का निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत भुगतान करना ही सबसे अच्छा रास्ता अथवा विकल्प है।

ह। भारत में तज गात से हा रहा आधिक प्रगति के चलते मध्यमवर्गीय नागरिकों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है, जिनके द्वारा चार पहिया वाहनों, स्कूटर, फिज, टीवी, वॉशिंग मशीन एवं मकान आदि आस्तियों को खरीदने हेतु बैंकों अथवा अन्य वित्तीय संस्थानों से ऋण लिया जा रहा है। कई बार मध्यमवर्गीय परिवार एक दूसरे की देखा देखी आपस में होड़ करते हुए भी कई उत्पादों को खरीदने का प्रयास करते हुए दिखाई देते हैं, चाहे उस उत्पाद विशेष की आवश्यकता हो अथवा नहीं। उदाहरण के लिए एक पड़ौसी ने यदि अपने चार पहिया वाहन का एकदम नया मॉडल खरीदा है तो जिस पड़ौसी के पास पूर्व में ही चार पहिया वाहन उपलब्ध हैं वह पुराने मॉडल के वाहन को बेचकर पड़ौसी द्वारा खरीदे गए नए मॉडल के चार पहिया वाहन को खरीदने का प्रयास करता है और बैंक के ऋण के जाल में फंस जाता है। यह नव धनाड्य वर्ग यदि बैंक से लिए गए ऋण की किश्त एवं ब्याज की राशि का निर्धारित समय सीमा के अंदर भुगतान नहीं कर पाता है तो उस नागरिक विशेष के वित्तीय रिकार्ड पर धब्बा लग सकता है जिससे उसके लिए उसके शेष जीवन में बैंकों एवं अन्य वित्तीय संस्थानों से पुनः ऋण लेने में कठिनाई आ सकती है। अतः बैंकों से ऋण प्राप्त करने वाले नागरिकों को ऋण की किश्त का समय पर भुगतना करना स्वयं उनके हित में है, ताकि भारत में तेज हो रही आर्थिक प्रगति का लाभ आगे आने वाले समय में भी समस्त नागरिक ले सकें।

